



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 785]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2003/भाद्र 6, 1925

No. 785]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2003/BHADRA 6, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
आदेश

मुम्बई, 28 अगस्त, 2003

का.आ. 991(अ).—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् “भाप्रविबो” के रूप में निर्दिष्ट) ने तारीख 12 फरवरी, 2003 के परिपत्र सं. एसएमडी/नीति/परिपत्र-6/03 द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को सलाह दी कि वे निपटान चक्र को 1 अप्रैल, 2003 से टी + 3 आवर्तन निपटान (रोलिंग सेटलमेंट) से छोटा करके टी+2 आवर्तन निपटान का करें और उक्त परिपत्र के जवाब में, भाप्रविबो को उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् एक्सचेंज के रूप में निर्दिष्ट) से तारीख 26 मार्च, 2003 के पत्र द्वारा एक्सचेंज की उप-विधियों की उप-विधि सं. 228(3) में संशोधन चाहने वाला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया गया है और अनुमोदन निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन प्रदान किया जाता है :

“सदस्य अपने घटकों को भुगतान करेंगे और जावक-भुगतान (पे-आउट) के 24 घंटों के भीतर खरीदी गई प्रतिभूतियों को परिदत्त करेंगे”।

यतः, एक्सचेंज ने ऊपर निर्दिष्ट पत्र द्वारा भाप्रविबो के तारीख 12 फरवरी, 2003 के परिपत्र सं. एसएमडी/नीति/परिपत्र-6/03 को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रस्तावित संशोधनों के पूर्व प्रकाशन के अधित्पजन के लिए भाप्रविबो का अनुमोदन मांगा और एक्सचेंज से प्राप्त अनुरोध पर विचार किया गया है और भाप्रविबो की राय है कि व्यापार के हित में और लोक हित में उपर्युक्त संशोधन एक्सचेंज में टी+2 आवर्तन निपटान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तुरन्त किया जाना चाहिए।

इसलिए, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भाप्रविबो एतद्वारा उप-विधि के पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति प्रदान करता है जैसा ऊपर अनुमोदित है।

[सं. रा./असा./01/एनआरओ]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

ORDER

Mumbai, the 28th August, 2003

S.O.991(E).—Whereas the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as “SEBI”) vide circular No.SMD/POLICY/Cir-6/03 dated February 12, 2003 advised the Stock Exchanges to shorten the settlement cycle from T+3 rolling settlement to T+2 rolling settlement with effect from April 1, 2003 and in response to the said circular, SEBI has received a proposal from Uttar Pradesh Stock Exchange Association Ltd. (hereinafter referred to as the Exchange) vide letter dated March 26, 2003 seeking amendment to bye-law no. 228(3) of the bye-laws of the exchange and the proposal received from the Uttar Pradesh Stock Exchange has been considered and approval is granted subject to the following modifications:

“Members shall make payment to their constituents and deliver the securities purchased within 24 hours of the payout”.

Whereas, the Exchange *vide* the above referred letter sought the approval of SEBI for waiver of prior publication of the proposed amendments in the official gazette in order to implement SEBI's circular no. SMD/POLICY/ Cir-6/03 dated February 12, 2003 and the request received from the exchange has been considered and SEBI is of the opinion that in the interest of the trade and in the public interest the above amendment should be made immediately for effective implementation of T+2 rolling settlement in the Exchange.

Therefore, in exercise of the powers conferred under Sub-section (4) of Section 9 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, SEBI hereby dispense with the condition of previous publication of the bye-law as approved above.

[No. G/E/01/NRO]

G. N. BAJPAI, Chairman